(c) what is the total amount likely to be spent on these schemes during the current financial year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON) : (a) Yes, Sir.

(b) Against the target of providing economic assistance to 9.21 lakh Scheduled Tribe families during the Seventh Plan, 6.81 lakh Scheduled Tribe families have been assisted during the first three years. No survey has been conducted in the State about the Scheduled Tribe families assisted to know the number who have crossed the poverty line.

(c) During the current year 1988-89, a total amount of Rs. 312.56 crores has been quantified by the State for Tribal Sub-Plan.

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी के निवासियों को नये राशनकार्ड जारी किया जाना

1202. श्री सुनील कुमार पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी के गरीब निवासियों को नए राशन कार्ड जारी किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उसके परिणामस्वरूप उनको खाद्य वस्तुएं खुले बाजार में अधिक कीमत देकर खरीदनी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों को नये राशन कार्ड जारी करने का विचार रखती है और क्या कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने इसका खंडन किया है और कहा है कि पात्र व्यक्तियों को नए स्थायी राशन कार्ड जारी किए जाते है । दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए नीति-संबंधी निर्णय के अनुसार, झुग्गी/झोंपड़ियों तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करके रहने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर अस्थायी कार्ड जारी किए जाते हैं । इस समय जैसाकि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को कोई अस्थायी कार्ड जारी नहीं किएजा रहे हैं ।

देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता

1203. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में खाद्यान्नों की राज्यवार आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस समय सरकार के विभिन्न सुरक्षित भण्डारों/भण्डार गृहों में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा उपलब्ध है ; और

(ग) निकट भविष्य में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमे वर्ष 1987 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा खाद्यान्नों के लिए की गई मांग का ब्यौरा दिया गया है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) पहली अप्रैल, 1988 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास कुल 94.3 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) देश के अन्दर वसूली अभियानों के जरिये तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है तब विदेशों से आयात कर स्टाक की नियमित रूप से भरपाई की जाती है ।

विवरण

वर्ष 1987 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों की मांग
(लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मांग
1	2
आन्ध्र प्रदेश	26.60
अरुणाचल प्रदेश	0.83
असम	11.98
बिहार	25.95
गोआ	0.72
गुजरात	12.40
हरियाणा	4.37
हिमाचल प्रदेश	2.12
जम्मू तथा कश्मीर	4.02
कर्नाटक	9.75
केरल	24.20
मध्य प्रदेश	9.75
महाराष्ट्र	18.80
मणिपुर	1.44
मेघालय	1.85
मिजोरम	1.29
नागालैण्ड	1.50
उड़ीसा	6.01
पंजाब	1.40
राजस्थान	8.09
सिक्किम	0.57
तमिलनाडु	16.10
त्रिपुरा	1.60
उत्तर प्रदेश	19.20
पश्चिम बंगाल	35.70
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.23
चण्डीगढ़	0.28
दादर तथा नगर हवेली	0.05
दमन तथा दीव	0.03
1	2
दिल्ली	9.45
लक्षद्वीप	0.06
पाण्डिचेरी	0.28

Production of Sugar

1204. SHRI KALPNATH RAI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the quantity of sugar produced and consumed in the country during the last financial year;

(b) whether the sugar produced was adequate for the country's needs or any quantity of sugar imported, if so, the quantity imported; and

(c) the steps being taken to increase sugar production in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): a) The sugar year is reckoned from October to September. During the 1986-87 sugar year, a quantty of 85.5 lakh tonnes (Provisional) was consumed in the country.

(b) To bridge the gap in availability and domestic requirement a quantity of 6.56 lakh tonnes (Provisional) of sugar was imported during the last financial year 1987-88.

(c) The sugar production during the current 1987-88 season upto 15-4-1988 was 76.44 lakh tonnes as against 73.16 lakh tonnes on the corresponding date last year.

Government has also initiated series of **measures to increase sugar production in the country such as :**

(1) Increase in statutory minimum price of sugarcane from Rs. 17 per **quintal in 1986-87 to Rs. 18.50 per quintal in 1987-88.**

(2) Advance announcement of statutory minimum cane price for 1988-89 season at Rs. 19 per quintal;